संपादकीय जागरण

रविवार, 29 जुलाई, 2018 : श्रावण कृष्ण 2 वि. 2075

एक सच सौ झूठ बोलने से बचा लेता है

नजीर बनने वाली कार्रवाई

घटनाओं-दुर्घटनाओं की तमाम खबरों के बीच यह खबर उल्लेखनीय है कि करीब दो माह पहले वाराणसी में फ्लाईओवर हादसे के सिलसिले में सात इंजीनियरों समेत एक ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि आम तौर पर इस तरह के मामलों में सरकारी कर्मियों के खिलाफ मुश्किल से ही कोई कार्रवाई होती है और अगर होती भी है तो इतनी देर में या फिर इतनी मामूली कि वह निष्प्रभावी ही सिद्ध होती है। वाराणसी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर की बीम गिरने से हुए हादसे के लिए जिन्हें जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार किया गया उनमें सेतु निगम के पूर्व और निवर्तमान मुख्य परियोजना प्रबंधक भी शामिल हैं। इससे यही रेखांकित होता है कि 15 लोगों की जान लेने वाले इस हादसे में शीर्ष स्तर के अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है। माना जा रहा है कि कुछ और लोगों पर भी पुलिस का शिकंजा कस सकता है, लेकिन बात तब बनेगी जब हादसे के लिए जिम्मेदार माने गए लोगों को सजा दिलाने में भी कामयाबी मिले। कोशिश यह होनी चाहिए कि यह कामयाबी जल्द हासिल हो, क्योंकि तभी इसका असर होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की यह कार्रवाई अन्य राज्यों के लिए एक नजीर भी बननी चाहिए। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में हुए इस हादसे की जांच में यह सामने आया था कि गर्डर की लॉकिंग के लिए क्रॉस बीम न ढाले जाने के कारण दो बीम राह चलते लोगों पर गिरीं। इस मामले में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि फ्लाईओवर निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई।

अपने देश में मानकों की अनदेखी करके होने वाला निर्माण एक राष्ट्रीय रोग बन गया है। फ्लाईओवर के साथ-साथ सड़कों, पुलों आदि के निर्माण में मानकों की जमकर अनदेखी भी होती है और उसके कारण हादसे भी। जो नहीं होता वह यह कि संबंधित सरकारी अधिकारियों से कोई जवाबदेही नहीं ली जाती। बहुत होता है तो उनका तबादला कर दिया जाता है या फिर संबंधित ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जाता है। निःसंदेह यह कोई दंड नहीं हुआ। इसका कोई मतलब नहीं कि मानकों की अनदेखी वाले निर्माण से हुए हादसों में लोगों की जान चली जाए और फिर भी किसी को दंड का भागीदार न बनाया जाए। पता नहीं अपने देश में यह कैसे एक चलन सा बन गया है कि निजी क्षेत्र के किसी उद्यम-कारखाने या अन्य स्थल में कोई हादसा हो तो जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब सरकारी स्थलों में ऐसा होता है तो मुश्किल से ही कोई जवाबदेह बनता है। कई बार जवाबदेही तय करने के नाम पर या तो लीपापोती होती है या फिर दिखावे की कार्रवाई। ऐसी जवाबदेही का कोई मतलब नहीं जिसमें किसी को दंड का भागीदार न बनाया जाए। निःसंदेह जब-तब मानवीय भूल भी हादसों का कारण बनती है, लेकिन आम तौर पर एक बड़ा कारण घटिया निर्माण कार्य ही होता है और ऐसे निर्माण कार्य के पीछे बड़ी भूमिका होती है कमीशनखोरी की। दरअसल इसी के चलते न जाने कितनी नई बनी सड़कें पहली बरसात में ही बह जाती हैं।

जर्जर इमारतें

एक हफ्ते में मकान गिरने की कई घटनाएं हुई हैं। ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद तक मकान भरभरा कर गिरे हैं। बरसात में पुराने और जर्जर मकानों के गिरने की घटनाएं तो पहले भी होती थीं, मगर इधर निर्माणाधीन इमारतें भी गिर रही हैं। स्थानीय लोग तो मलबे में दबे लोगों को निकाल ही रहे हैं, सरकार भी राहत कार्य कर रही है, पुलिस, अग्निशमन दल से लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी जूझना पड़ रहा है। मृतक के परिवारीजन को सहायता राशि दी जा रही है, घायलों के इलाज और मुआवजे का इंतजाम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश को देखते हुए आमजन को सतर्क करने के लिए जिला प्रशासनों को निर्देश दिए हैं।

सरकार के सामने पुराने और जर्जर मकानों की समस्या तो है ही, नए मकानों की गिरती गुणवत्ता ने भी परेशानी पैदा कर दी है

देखने में आ रहा है कि महानगरों से शुरू हुआ बहुमंजिला इमारतें बनाने का क्रम अब छोटे शहरों तक पहुंच गया है। मुख्य सड़कों से लेकर खेतों तक में कई मंजिल के भवन खड़े हो चुके हैं। लोगों में अपार्टमेंट में रहने की ललक बढ़ रही है। मुख्य दरवाजे पर गेट मैन, सीढ़ियां चढ़ने का झंझट खत्म, साफ-सफाई के लिए छोटा सा एरिया और पावर बैकअप जैसी सुविधाएं लोगों को लुभा रही हैं। नोटबंदी के बाद से रीयल स्टेट बैकफुट पर है, ऊपर से नियामक कानून 'रेरा' का चाबुक। मंदी के इस दौर में कीमत कम रखना भी मजबूरी है। ऐसे में सवाल स्वाभाविक है कि कहीं इमारत निर्माण के मानकों से समझौता तो नहीं हो रहा। सरकार के सामने पुराने और जर्जर मकानों की समस्या तो है ही, नए मकानों की गिरती गुणवत्ता ने भी परेशानी पैदा कर दी है। प्राधिकरणों के पास अधिकार है कि इमारत का नक्शा पास करें और पूर्ण होने एवं रहने लायक होने का प्रमाण पत्र जारी करें फिर भी ये दुर्घटनाएं हो रही हैं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने से भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधरेंगे?

आज का सवाल
क्या डाटा चोरी पर भारी जुर्माना लगाने से डाटा सुरक्षा बढ़ेगी उसके दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा?

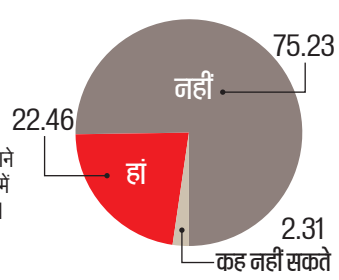

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल

संजय गुप्त

यदि सोशल मीडिया कंपनियां आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग से यह जानने में सफल हैं कि किस यूजर की क्या पसंद है तो वे यह भी जान सकती हैं कि किस यूजर ने नफरत फैलाने वाली सूचना फैलाई

मानव सभ्यता के विकास में सूचनाओं का आदान-प्रदान एक अहम पहलू है। सूचनाओं का यह आदान-प्रदान अलग-अलग तरीकों से प्राचीन काल से चला आ रहा है। समाचार पत्रों के उदय के साथ इसने एक संस्थागत रूप ग्रहण किया। समाचार पत्रों के माध्यम से नियंत्रित तरीके से सूचनाएं आम लोगों तक पहुंचने लगीं। समाचार पत्रों के बाद रेडियो और फिर टेलीविजन ने इस क्रम को तेज किया। प्रारंभ में टेलीविजन पर सरकारों का नियंत्रण रहा, लेकिन धीरे-धीरे इस माध्यम की कमान निजी हाथों में भी आ गई। इसके चलते सूचनाओं का आदान-प्रदान कुछ लोगों के लिए एक व्यवसाय बना तो कुछ ने इसे सामाजिक चेतना का हथियार बनाया। यह एक तथ्य है कि अधिकतर समाचार पत्र और टीवी चैनलों का संचालन करने वाले मीडिया समूहों ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा और इसके प्रति सचेत रहे कि समाज के लिए उपयोगी सूचनाओं का ही प्रचार-प्रसार हो। कंप्यूटर आने के साथ ही सूचना संसार में एक क्रांति सी आई। इंटरनेट की खोज ने इस क्रांति को नया मुकाम दिया। शुरुआत में कुछ क्षेत्रों और लोगों तक सीमित रहे इंटरनेट को जल्द ही सभी ने अपना लिया। सच तो यह है कि यह सभी की जरूरत बन गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसे अपनी कार्यप्रणाली का हिस्सा बना लिया। इनमें सरकारें और उनका प्रशासनिक तंत्र भी शामिल है। सर्च इंजन गूगल ने सूचनाएं हासिल करने के काम को और आसान बना दिया। इसमें संदेह नहीं कि इंटरनेट ने विकास को नए आयाम दिए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के उभार ने इंटरनेट को लेकर कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सबसे गंभीर सवाल अश्लीलता के प्रसार और निजता के हनन को लेकर हैं। इन सवालों पर भारत समेत पूरी दुनिया में बहस चल रही है। इस बहस के बीच लोगों की निजी जानकारी लीक होने या चोरी करने की खबरें आ रही हैं। चूंकि इसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है इसलिए उसकी सुरक्षा एक समस्या बन गई है। एक अन्य समस्या सोशल मीडिया के जरिये फैल रहा नफरत और दुष्प्रचार भी है।

आज सोशल मीडिया का सबसे सशक्त और व्यापक प्लेटफार्म फेसबुक है। फेसबुक के साथ ट्विटर, वाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे माध्यम भी खासे लोकप्रिय हैं। वाट्सएप फेसबुक की ही एक कंपनी है। यह आपस में संपर्क-संवाद का और साथ ही सूचनाएं पहुंचाने का सबसे सरल और प्रचलित माध्यम है। सोशल मीडिया ने जहां समाज के हर व्यक्ति को यह मौका दिया कि वह अपनी बात एक खुले मंच पर रख सके वहीं अब पिछले कुछ सालों से इसके तमाम नुकसान भी देखने में आ रहे हैं। चूंकि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म सभी को सहज उपलब्ध हैं इसलिए आतंकी, अतिवादी और अन्य अवांछित तत्वों को उनका इस्तेमाल करने से रोकना कठिन हो रहा है। तमाम आतंकी संगठन और खास तौर पर आइएस अपने प्रचार-प्रसार के लिए केवल सोशल मीडिया पर ही निर्भर है। वैसे तो झूठी खबरों और नफरत फैलाने वाली बातों का प्रसार सोशल मीडिया के सभी माध्यमों से हो रहा है, लेकिन इस मामले में सबसे कुख्यात वाट्सएप है। अपने देश में भीड़ की हिंसा के कई मामलों में यह सामने आया कि वाट्सएप से इस आशय की झूठी सूचनाएं फैलाई गईं कि अमुक जगह बच्चा चोरी करने वाले सक्रिय हैं। इसी तरह कई जगह अशांति इसलिए बनी, क्योंकि नफरत फैलाने वाला कोई संदेश प्रसारित किया गया था। आम धारणा है कि वाट्सएप झूठी खबरें यानी फेक न्यूज के प्रसार का पसंदीदा माध्यम बन गया है। इसी कारण सरकारों को इस माध्यम के दुरुपयोग को रोकने के उपाय सोचने पड़ रहे हैं। ध्यान रहे कि इस माध्यम की तकनीक भी ऐसी है कि किसी अन्य के लिए सूचनाओं को पढ़-समझ पाना कठिन है।

अवधेश राजपूत

फेसबुक और वाट्सएप संचालित करने वाले मार्क जुकरबर्ग अपने व्यावसायिक हितों के चलते सूचनाओं के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए तैयार नहीं। यही स्थिति अन्य सोशल मीडिया कंपनियों की भी है। इनका तर्क है कि उनका प्लेटफार्म सबके लिए है और वे किसी को अपनी बात कहने से रोक नहीं सकते। यह बात और है कि जब ये कंपनियां किसी समस्या से घिरती हैं तो अपना सुर बदल लेती हैं। हाल में अपने यूजर्स के डाटा लीक को लेकर बुरी तरह घिरने के बाद फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भविष्य में ऐसा न होने देने का वायदा किया। फेसबुक यूजर्स का डाटा लीक होने का मामला भारत से भी जुड़ा है। चुनावी लाभ के लिए फेसबुक यूजर्स की निजी जानकारियां कैंब्रिज एनालिटिका कंपनी को बेची गईं। एक गंभीर मामला होने के कारण सरकार ने इसकी जांच सीबीआइ से कराने का फैसला किया है।

चूंकि सोशल मीडिया कंपनियों का व्यावसायिक हित इसी में है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके माध्यम का इस्तेमाल करें इसलिए यही उनका बिजनेस मॉडल बन गया है। इसी के जरिये वे अरबों-खरबों कमा रही हैं। टेलीकॉम कंपनियां भी इसी तर्ज पर काम कर रही हैं। जब मोबाइल फोन नए-नए आए थे तब उनकी कॉल दरें इतनी महंगी थीं कि लोग कॉल करने से भी बचते थे और कॉल रिसीव करने से भी। धीरे-धीरे पहले कॉल दरें लगातार कम हुईं और फिर डाटा की दरें। अब तो कॉल और डाटा दरें लगभग मुफ्त हो चली हैं। परिणाम यह है कि लोग मोबाइल पर गैर जरूरी बातें करने में घंटों खपा देते हैं। डाटा के इस्तेमाल में भी यही स्थिति है। चूंकि सब कुछ करीब-करीब मुफ्त में उपलब्ध है इसलिए लोग कुछ न कुछ देखते-सुनते रहते हैं या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म में बेवजह सक्रिय रहते हैं। इस दौरान ही वे जाने-अनजाने झूठी खबरों के प्रचार-प्रसार में सहायक बनते हैं। कई बार शरारती और अतिवादी तत्व जानबूझकर नफरत फैलाने के लिए तरह-तरह की झूठी खबरें गढ़ते या फिर उन्हें प्रसारित करते हैं। सोशल मीडिया कंपनियां ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में आनाकानी करती हैं। वे ऐसा इसलिए करती हैं, क्योंकि उनका व्यावसायिक हित प्रभावित होता है। यही स्थिति टेलीकॉम कंपनियों की है। वे डाटा को तेल की तरह मानकर भारी-भरकम निवेश तो कर रही हैं, लेकिन इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं कि उनका बिजनेस मॉडल समाज और सरकारों के लिए समस्या बन रहा है।

अगर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के बेजा इस्तेमाल पर लगाम लगानी है तो सूचनाओं के आदान-प्रदान की कोई ऐसी कीमत तय करनी होगी जिससे लोग उसका बेवजह या फिर अनुचित इस्तेमाल करने से बचें। इससे पूरी तौर पर तो नहीं, कुछ हद तक सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरुपयोग थमेगा। इसी के साथ सोशल मीडिया कंपनियों को इसके लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि वे नफरत फैलाने वालों की जानकारी देने के लिए तैयार रहें। यदि वे आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग का सहारा लेकर यह जानने में सफल हैं कि किस यूजर की क्या पसंद है तो वे यह भी तो जान सकती हैं कि किस यूजर ने नफरत फैलाने वाली सूचना फैलाई। बेहतर होगा कि इस पर गौर किया जाए कि हर चीज की अति बुरी होती है और इसमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल भी है।

response@jagran.com

स्विस बैंक में खाली होते हमारे खाते

हास्य-व्यंग्य

पीयूष पांडे

स्विस बैंक ने भारतीयों की राशि का जो आंकड़ा दिया है उसे सुनकर तो आला दर्जे का भ्रष्टाचारी खुदकुशी कर ले

दुनियाभर में हजारों बैंक हैं, लेकिन स्विस बैंक का अलग जलवा है। जिस तरह तमाम सुंदरियां होती हैं, लेकिन बातों में, किस्सों में, अफवाहों में कोई एक खास सुंदरी ही होती है, कुछ वैसा ही हाल स्विस बैंक का है। करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए स्विस बैंक उसी तरह एक अबूझ पहेली है, जिस तरह 'बांछें खिली हुई हैं' में बांछें कहां होती हैं एक पहेली है। वैसे ही स्विस बैंक नाम की इस अबूझ पहेली से पड़ोसी वर्मा जी भी बचपन से जूझ रहे थे।

चूंकि वर्मा जी पिछली सदी से मेरे पड़ोसी थे तो घर में बेहिचक कभी भी घुस आने को जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। इसी अधिकार का पालन करते हुए कल सुबह सुबह वह आए और बोले, 'यार स्विस बैंक में भारतीयों के तीन सौ करोड़ रुपये पड़े हैं। उनका कोई लेनदार नहीं। कोई एफिडेविट बनवाकर हम दावा ठोंक सकते हैं क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। सरकार पूछेगी कि कहां से आए तो बोलेंगे कि परदादा छोड़ गए थे। बाकी आप अपना टैक्स काट लो। हमें नंबर एक में दे दो, जितना हमारा बनता है।'

मैंने कहा, 'आप बिजली विभाग में बाबू हैं, फिर भी इतने भोले हैं या ऐसी बातें करके जानबूझकर मेरा इम्तिहान लेते हैं।'

वह बोले, 'यार, मजाक कर रहा था। स्विस बैंक एक फैंटेसी है। न जाने कब से ख्वाब रहा है कि एक खाता स्विस बैंक में हो। हम भी सीना तानकर कह सकें कि हमारा अकाउंट भी स्विस बैंक में है, लेकिन, किस्मत ऐसी खराब रही कि पूरी जिंदगी स्विस बैंक खाते के ख्वाब में ही कट गई।'

'इतनी जल्दी निराश न हों, आप। रिश्वत का एक कायदे का मौका हाथ लग गया तो जिंदगी बदल सकती है। आप कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वैसे, भारतीय बैंक भी अब स्विस बैंक सरीखे हो लिए हैं। सरकार को कुछ नहीं बताते। करोड़ों डकारकर बंदा जब लंदन में ऐश करते हुए तस्वीर ट्विटर पर डालता है तब सरकार को पता चलता है कि लो जी ये तो भाग गया। बैंकों के 10 हजार, 20 हजार करोड़ लेकर। बाकी स्विस बैंक में अब भारतीयों की दिलचस्पी कम हो रही है।' मैंने कहा।

उन्होंने कहा, 'कैसे?'

मैंने कहा, 'स्विस बैंक ने भारतीयों की जमा रकम का अभी जो आंकड़ा जारी किया है वह ऐसा है कि आला दर्जे का भ्रष्टाचारी सुनकर खुदकुशी कर ले। सच्चा कमीशनखोर स्विस बैंक पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दे। सच्चा दलाल आंकड़ों की गलतबयानी के लिए स्विस बैंक को संयुक्त राष्ट्र में खींच ले। स्विस बैंक ने रकम बताई है सात हजार करोड़ रुपये। यह भी कोई रकम हुई भला। भारतीयों का जितना पैसा स्विस बैंक में जमा बताया जा रहा है, उससे ज्यादा तो किसी भी भ्रष्ट अफसर के घर से कभी भी बरामद की जा सकती है।

वह बोले, 'स्विस बैंक में भारतीयों की कम से कम 412242443343348834344 करोड़ की रकम होनी चाहिए। ऐसी रकम, जिसे पढ़ना मुश्किल हो। ऐसी रकम, जिसे बुदबुदाते हुए भ्रष्ट भारतीयों को लेकर सम्मान का भाव जागे।'

मैंने उनकी हां में हां मिलाते हुए कहा, 'सरकार को खुद स्विस बैंक के इस आंकड़े को खारिज करना चाहिए। यह देश की प्रगति के मॉडल के खिलाफ है। प्रगति होगी तो अधिकारियों के, दलालों के, नेताओं के बैंक अकाउंट मजबूत होंगे ही। लेकिन, स्विस बैंक ने जो आंकड़ा दिया है वह जताता है कि अधिकारियों की, नेताओं की, दलालों की जेब खाली पड़ी है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार का दावा है कि काम बहुत हो रहा है। और काम होगा तो अधिकारियों के अकाउंट भरेंगे ही।'

वह मेरी बात से सहमत थे। बोले, 'वैसे, स्विस बैंक का आंकड़ा प्रधानमंत्रीजी के उस आंकड़े से भी नहीं मिलता, जिसमें कहा गया था कि विदेशों में जमा सारा कालाधन वापस आ जाए तो हर भारतीय के खाते में कम से कम 15 लाख रुपये आ जाएंगे। 7 हजार करोड़ तो कोई रकम ही नहीं।'

मैंने कहा, 'आपका गणित जोरदार है।'

वह बोले, 'पैसा लेते वक्त हर बाबू का गणित जोरदार ही रहता है। वैसे, काश अकाउंट में 15 लाख आ जाते तो।'

मैंने कहा, 'क्या पता, आ ही जाएं। जिस वक्त 15 लाख की बात कही गई थी, अगर उस वक्त पीएम की जुबां पर सरस्वती बैठी हो तो बात सच होकर रहेगी। आज नहीं तो कल। वैसे, क्या पता विदेशों में जमा सारा काला धन सरकार वापस पहले ही ले आई हो। क्या पता उस पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया हो और चुनाव के वक्त हर खाते में 15 नहीं 30 लाख आ जाएं। क्या पता?

वह भी बोले-'क्या पता? शायद इसीलिए स्विस बैंक में महज 7000 करोड़ रुपये की ही चिल्लर बची रह गई हो।'

'क्या पता?' मैं भी बोल पड़ा।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | सोने का आयात

अरब डॉलर

स्रोत : वाणिज्य मंत्रालय

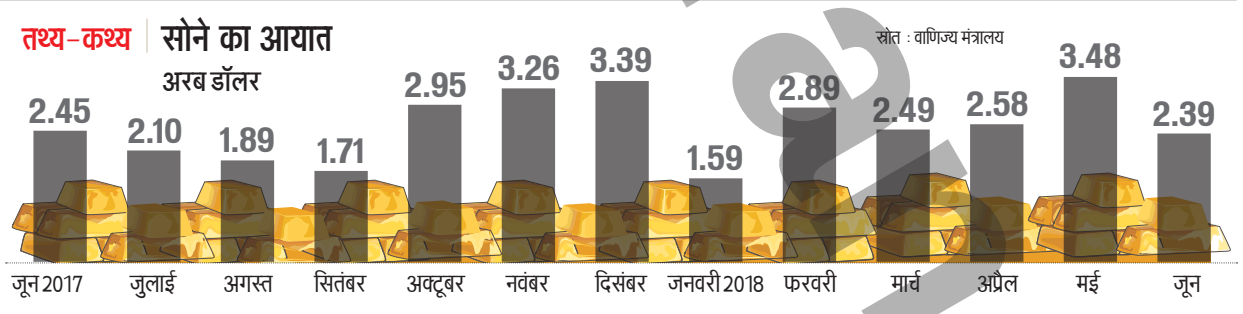

ऊर्जा

आत्मविश्वास

कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आत्मविश्वास हमें दृढ़ता प्रदान करता है। किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें उसके द्वारा अर्जित छोटी-छोटी उपलब्धियों पर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है तो भी उसे आगे बढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो उसका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। आत्मविश्वास की वजह से व्यक्ति असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव कर देता है। प्रशंसा एक उपहार है, जिसका परिणाम सदैव आनंदमय होता है। वैसे कई बार आत्मविश्वास इंसान पर हावी होकर अभिमान में भी परिवर्तित हो जाता है। आत्मविश्वास से व्यक्ति नित्य नई ऊंचाइयों को छूता है जबकि अभिमानी व्यक्ति एक दायरे में सिमटकर रह जाता है।

किसी कार्य को करने में हम किस स्तर तक सफल होंगे इसका आभास हमें शुरुआत में ही हो जाता है। ऐसा हमारे आत्मविश्वास के कारण होता है। यदि कार्य शुरू करते वक्त हमारे अंतर्मन से आवाज आती है कि हम इसे कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर उस कार्य को करने में हम काफी हद तक सफल रहते हैं। इसके विपरीत यदि हम शुरुआत में यह मानने लगें कि यह कार्य हमसे नहीं होगा तो हो सकता है कि हम बेकार ही उस कार्य को शुरू ही न कर सकें। आत्मविश्वास का अर्थ स्वयं पर विश्वास करना है। यदि हमें अपने ऊपर यकीन है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। जब हम आत्मविश्वास के साथ कोई कार्य करते हैं तो उसमें मिली असफलता भी हमें दुख नहीं देती। ऐसा इसलिए, क्योंकि कार्य को करने की खुशी उसी क्षण मिल जाती है। आत्मविश्वासी व्यक्ति हर समस्या व संघर्ष को चुनौती के रूप में ले लेता है। बड़े काम करने के लिए आत्मविश्वास पहली सीढ़ी है। खुद पर यकीन करो और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। अपनी क्षमता पर विश्वास किए बिना आप सफल या खुश नहीं रह सकते। आप अंदर से चाहें कैसा महसूस करें, पर खुद को हमेशा एक विजेता की तरह दिखाने की कोशिश कीजिए। आप आत्मविश्वास के साथ मानसिक बढ़त हासिल कर सकते हैं। यह बात निश्चित है कि आत्मविश्वास के बिना साहस नहीं आ सकता।

पूर्णिमा अग्रवाल

बिल से पहले की क्लास

अक्सर ऐसा नहीं होता। लेकिन इस बार सरकार के एक मंत्री को सदन में अपना विधेयक रखने और उसे पारित कराने के लिए विपक्ष के एक नेता की मदद लेनी पड़ी। इन मंत्री जी को लोकसभा में अपने मंत्रालय से संबंधित एक कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश करना था, लेकिन मामला कुछ ज्यादा पेचीदा था। लिहाजा संसद के सेंट्रल हॉल में उन्होंने विपक्ष के एक ऐसे नेता को पकड़ा जो आर्थिक और वित्तीय मामलों में काफी दखल रखते हैं। मंत्री जी ने इन नेता से अनुरोध किया कि उन्हें सदन में विधेयक पर कुछ बोलना होगा लिहाजा इस विषय पर उनसे समझना चाहते हैं। विपक्ष के सांसद महोदय ने मंत्री जी को भरोसा दिया कि वह सब कुछ समझा देंगे। उन्होंने बताया भी, लेकिन बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। मंत्री जी विधेयक पेश होने से पूर्व भी सदन में विपक्ष की बेंच पर उस सांसद के साथ बैठे दिखाई भी दिए।

गलती ढूढ़ने में बुरे फंसे

सांसदों के बीच गूगल बाबा के नाम से विख्यात तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद आजकल सदन के भीतर मंत्रियों की गलतियां ढूंढने में जुटे रहते हैं। यह अलग बात है कि बार-बार उन्हें खुद ही अपनी गलती पर शर्मिंदा होना पड़ता है। लोकसभा में इस प्रोफेसर साहब में एक मंत्री के लिखित जवाब को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जबकि जवाब में इसे उत्तराखंड में बताया है। वैसे मंत्री ने तत्काल उन्हें बताया कि एक गोरखपुर उत्तराखंड में भी है और बात उसी की हो रही है। इसी तरह प्रोफेसर साहब में यूजीसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में गलती निकालते हुए प्रकाश जावड़ेकर को गलत साबित करने की कोशिश की। उनका कहना था कि लिखित जवाब में प्रीडेटरी जर्नल लिखा है। जबकि ऐसा जर्नल होता ही नहीं है। आखिरकार जावड़ेकर को उन्हें भरे सदन में समझाना पड़ा कि प्रीडेटरी जर्नल होता है।

राजरंग

छवि की चिंता

लंबे अरसे से लोकसभा और राज्यसभा में रहे एक क्षेत्रीय दल के सांसद ने हाल ही में जब लोकसभा से इस्तीफा दे दिया तो उनके व्यवहार ने उनके अपने स्टाफ को अचंभे में डाल दिया। हुआ यूं कि इस्तीफा देने के बाद अगले दिन संसद भवन जाने से पहले उन्होंने अपने निजी स्टाफ से पूछना शुरू किया कि वह अब वहां जा भी सकते हैं या नहीं। और जाएंगे तो क्या आम लोगों की तरह उन्हें भी सुरक्षा व्यवस्था से गुजरना होगा? निजी स्टाफ की तरफ से उन्हें आश्वस्त किया कि वे बिना किसी हिचक सेंट्रल हॉल तक जा सकते हैं। इसके बावजूद वह सांसद महोदय जब संसद भवन पहुंचे तो इधर उधर जाने से कतराते रहे। यही नहीं उन्होंने अपने स्टाफ को यह भी हिदायत दे दी कि वे जल्द से जल्द उनके लिए लुटियन दिल्ली में घर खोज लें। हालांकि उनके स्टाफ ने समझाया कि वह चाहें तो कुछ दिन सरकारी आवास को अपने पास रख सकते हैं। लेकिन सांसद महोदय हैं कि मानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वह बेवजह चर्चा में आ जाएंगे और उनकी साफ छवि इससे प्रभावित होगी।

बेरुखे कमांडर

कांग्रेस के दिग्गज पी चिदंबरम ने सूबों में जमीनी सियासत मजबूत कर अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी के 150 सीटों तक पहुंचने की उम्मीद जरूर जताई है। मगर सूबों में पार्टी की चुनावी रणनीति की कमान संभाल रहे कुछ एक सियासी कमांडरों का रवैया कांग्रेस की इन उम्मीदों को पलीता लगा सकता है। पार्टी के गलियारों में कांग्रेस के नेता-कार्यकर्ता ही ऐसे चुनावी कमांडरों की कार्यशैली और गुरूर पर सवाल उठा रहे हैं। चिदंबरम ने जिन 12 राज्यों में कांग्रेस के अपने बूते जीतने का खाका पेश किया था उनमें तेलंगाना भी शामिल है। लेकिन पार्टी मुख्यालय के गलियारे में सूबे से आने वाले नेता-कार्यकर्ता केवल संगठन पर काबिज लोगों की सियासत का ख्याल रखने व खुद की अनदेखी का दर्द बयान करते दिखे। इशारे-इशारे में पार्टी के राज्य प्रभारी की बेरुखी पर वह बेलाग टिप्पणी करने से नहीं चूके। मंत्री दर्जे की हैसियत में रह चुके सूबे के एक पुराने नेता ने तो यह कहने से भी गुरेज नहीं कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को अहमियत देने की वकालत कर रहे हैं, मगर प्रभारी हैं कि मिलकर चर्चा करना तो दूर एसएमएस तक का जवाब नहीं देते। जाहिर है कि पार्टी के गलियारों में यह सवाल उठना लाजिमी है कि ऐसे सियासी कमांडर चुनावी नैया भला कैसे पार करा पाएंगे?

ट्वीट-ट्वीट

हिंदी भाषा पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। हिंदी का कई वर्षों तक विरोध किया गया, किंतु जब यह स्पष्ट हो गया कि हिंदी से धनोपार्जन भी संभव है तो विदेशियों तक ने हिंदी सीखी। हिंदी को प्रगति की भाषा बनाने का प्रयास करना चाहिए और सभी भारतीय भाषाओं को भी।

गौरव सी सावंत@gauravcsawant

अलगाववादियों और उनके समर्थक अनुच्छेद 35ए के हटने को लेकर बुरी तरह सहमे हुए हैं। चूंकि अनुच्छेद 35ए और धारा 370 के हटने से दुष्प्रचार चलाने की उनकी दुकान बंद हो जाएगी तो यह डर स्वाभाविक है। अब सभी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। आदित्य राज कौल@AdityaRajKaul

इमरान खान पाकिस्तान को सातवीं सदी का मदीना बनाना चाहते हैं। ऐसे में अच्छी बात यही है कि शासन की बागडोर उनके नहीं, बल्कि सेना के हाथ में रहेगी। उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान को दोजख बनाने के उनके मंसूबे परवान न चढ़ने पाएं। तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

राफेल सौदे पर तथ्यों को छुपाने के लिए मोदी सरकार कितना झूठ बोलेगी। मुझे लगता है कि अपना कार्यकाल समाप्त होने तक यह सरकार झूठ और फर्जी वादों के मामले में नए कीर्तिमान बना देगी।

अशोक गहलोत@ashokgehlot51

जनपथ

बाउंसर मत फेंकना भारत पर इमरान,
सिक्सर जड़ देगा यहां भारत का कप्तान।
भारत का कप्तान नहीं है ढीला ढाला,
खुराफात बिसराय शांति की जपिए माला।
सेना कर मिसफील्ड आपका फुड़वाए सर,
उससे बेहतर आप भूल जाओ बाउंसर।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। **वर्ष 29 अंक 12**